भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2749
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए राज्यों को निधि प्रदान करना

2749. श्री सतीश कुमार गौतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने/ तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को निधि प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख) **:** वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में 'वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना' का अनुमोदन किया गया था। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है।

नीति का अनुसरण करते हुए एवं विकास को गति देने के लिए**,** 'विशेष केंद्रीय सहायता **(**एससीए**)** योजना' के तहत पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए राशि प्रदान की जाती हैं। 2017 में योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों को लगभग ₹ 4289.20 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2749, दिनांक 04.08.2026

इस योजना के अलावा**,** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सम्बंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ मिलकर विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। विकास के उपायों पर की गई इन पहलों में से कुछ नीचे दी गई हैं**:**

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं**,** अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 15194 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 9561 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केन्द्र **(**एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) संचालित किए गए है।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6025 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1804 बैंक शाखाएं और 1321 एटीएम खोले गए हैं।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2749, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक-I

विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत जारी धनराशि

राज्य	जारी की गई राशि (रु करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	110.33
बिहार	462.53
छत्तीसगढ़	1715.83
झारखण्ड	1454.17
महाराष्ट्र	112.68
ओडिशा	268.99
तेलंगाना	128.21
केरल	2.50
मध्य प्रदेश	33.96
कुल	4289.20

****